एमएसएमई को सहारा औद्योगिक विकास को गति

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत निवेश कर रही कंपनियों और उद्यमियों को भी मिलेगा फायदा

96 लाख
यूपी की एमएसएमई इकाइयों को होगा लाभ

केंद्रीय बजट से यूपी में स्थापित 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को जहां सहारा मिलेगा, वहीं प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत यूपी में निवेश करने वाले निवेशकों को भी बजट घोषणाओं का बड़ा फायदा मिलेगा। जानकारों का कहना है कि एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी।

आम बजट में एमसएमई और औद्योगिक इकाइयों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इनमें एमएसएमई सेक्टर के लिए 9 हजार करोड़ का बजट देने, एक फीसदी कम ब्याज दर पर ऋण और एमएसएमई के लिए दो लाख करोड़ के कर्ज बांटने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। राज्य सरकार का भी एमएसएमई और औद्योगिक विकास पर फोकस है। इसके तहत 10-12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन प्रस्तावित है। इसमें करीब 17 लाख करोड़ रुपये निवेश की उम्मीद है।

एमएसएमई इकाइयों के उत्पादों की बढ़ेगी मांग

सीआईआई यूपी के अध्यक्ष विनम्र अग्रवाल का मानना है कि सरकार ने बजट में हरित विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है। इसके तहत ग्रीन एनर्जी, नवीनीकृत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की बात की गई है। नए एयरपोर्ट निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट और ऊर्जा के क्षेत्र में नए काम होने से एमएसएमई इकाइयों के उत्पादों की मांग बढ़ेगी।

- कोरोना काल में तमाम एमएसएमई इकाइयों की ओर से सरकारी विभागों में माल की आपूर्ति नहीं हो सकी थी। इससे विभागों ने टेंडर की शर्तों के अनुरूप उनकी लाखों रुपये की अमानत राशि जब्त कर ली।
- बजट में जब्त अमानत राशि में से 95 फीसदी तक लौटाने की घोषणा की है। इससे एमएसएमई सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। सरकार ने कौशल विकास पर फोकस किया है, इससे इंडस्ट्री को उनकी आवश्यकता के अनुरूप दक्ष श्रम एवं युवा शक्ति मिलेगी।

उद्यमियों का कहना है कि केंद्रीय बजट से यूपी में मौजूदा एमएसएमई इकाइयों को तो फायदा होगा ही, नई इकाइयों की स्थापना में भी तेजी आएगी।

01% छूट ऋण पर मिलेगी एमएसएमई इकाइयों पर

03% छूट ऋण पर देने की मांग कर रहे हैं एमएसएमई उद्यमी

टैक्स में छूट से मिलेगी राहत

आईआईए के अध्यक्ष आशोक अग्रवाल का कहना है कि एमएसएमई इकाइयों को ऋण पर एक प्रतिशत की छूट देने से बड़ा सहारा मिलेगा। हालांकि उद्यमी 3 प्रतिशत तक छूट चाहते थे। सरकार ने छूट भले ही एक फीसदी रखी है, लेकिन रेलवे, एयरपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट सहित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट पर फोकस से एमएसएमई को बड़ा कारोबार मिलेगा।

- सरकार ने वर्गीकरण की नई नीति की बात कही है, इससे लगता है कि अब एसएमएमई की लकड़ी की मांग की पूर्ति आसान होगी। तीन करोड़ रुपये वार्षिक टर्नओवर वाली इकाइयों को टैक्स में 5 फीसदी की छूट दी है। इससे यूपी की करीब 80 लाख से अधिक इकाइयों को फायदा होगा। एमएसएमई में 80 फीसदी तक डिजिटल लेनदेन करने वाली इकाइयों को भी टैक्स में पांच प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है, जो सराहनीय है।

यूपी में तेजी से हो सकेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास

33.4
फीसदी बजट केंद्र सरकार ने इस मद में बढ़ाया

यूपी में वर्तमान में एनएचएआई की 27 परियोजनाओं पर विभिन्न स्तरों पर चल रहा काम

लखनऊ। इंफ्रास्ट्रक्चर मद में केंद्र सरकार की ओर से बजट में 33.4 फीसदी वृद्धि से यूपी को पहले से अधिक बजट मिलने की उम्मीद है। इससे हाईवे समेत इन्फ्रास्ट्रक्चर की तमाम परियोजनाओं में तेजी आएगी। इस मद में कुल 10 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

केंद्र का जोर शहरी क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने पर है, ताकि नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के साथ-साथ आर्थिक विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा की अवधि बढ़ाने से भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। इस ऋण के साथ शर्त है कि इसके एक निश्चित भाग का इस्तेमाल ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए ही किया जाएगा। राज्यों के राजकोषीय घाटे के 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में पूंजीगत निवेशों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे ऊर्जा आपूर्ति और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार की संभावना है। केंद्र ने राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन सुधारों एवं कार्यों को प्रोत्साहन की घोषणा भी की है। यूपी में वर्तमान में एनएचएआई की 27 परियोजनाओं पर विभिन्न स्तरों पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं की रफ्तार भी अगले वित्त वर्ष में बढ़ सकेगी। ब्यूरो